6. अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की भरती के लिए मध्य प्रदेश में पांच भरती केन्द्र हैं। ये भरती केन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:—

(1) मुख्यालय भरती अंचल, जबलपुर।
(2) शाखा भरती कार्यालय, भोपाल
(3) शाखा भरती कार्यालय, ग्वालियर
(4) शाखा भरती कार्यालय, महू
(5) शाखा भरती कार्यालय, रायपुर

7. नौसेना तथा वायुसेना का अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए मध्य प्रदेश में कोई भरती केन्द्र नहीं है। मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में अफसरों के लिए नौसेना का एक चयन केन्द्र है।

हथकरघा क्षेत्र में रोजगार

*518. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की संभावनाएं कपड़ा मिल और विद्युत चालित करघा क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय देश में हथकरघा विद्युत चालित करघा और कपड़ा मिल क्षेत्रों में कितने-कितने लोग कार्यरत होकर अपनी-अपनी आजीविका कमा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) हथकरघा क्षेत्र वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक रोजगार मुहैया करता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्र में अनुमानतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार में क्रमशः 124.00 लाख तथा 77.9 लाख जबकि वस्त्र मिल क्षेत्र में अनुमानतः 10.3 लाख को रोजगार प्रदान होता है। सरकार प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनायें कार्यान्वित करने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने में सुविधा प्रदान करती है।

Shortage of Hotel Accommodation

*519. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of hotel rooms sand approved hotel accommodation;

(b) if so, the agency which studies and determines the extent of shortage of approved hotel accommodation;

(c) the manner in which Government propose to meet this challenge from tourism point; and

(d) the details of steps proposed to be taken in 1998-99?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): (a) In the approved sector, the Ministry of Tourism had estimated requirement of 1.25 lakh hotel rooms by 2000 A.D. Presently there are about 65000 hotel rooms which are already functioning and another about 47000 hotel rooms are in various stagtes of completion. The estimated shortage is likely to be about 13000 rooms.

(b) The Ministry of Tourism assigns specialised agencies to take up studies for forecasting the accommodation scenario for the future. In 1995 TAFSIL (Tourism Advisory and Financial Services Corporation Limited) was assigned the task of estimating the requirement for accommodation. This study was undertaken in close cooperation with Tourism Finance Corporation of India.

(c) and (d) Since the construction of hotels is a private sector activity, as a facilitator the Government of India extends fiscal benefits, duty concessions as well as interest subsidy to catalyse the private investment in the sector. The Government of India has also liberalised guidelines and procedures for foreign investment and foreign collborations for attracting investment in the sector. The Ministry of Tourism is in touch with other various Ministries / Departments as well as the State Governments for extending various incentives and benefits as well as for rationalisation of taxes levied on the industry. The Ministry of Tourism is also in touch with the State Governments through the Ministry of Urban Development for identification of land for hotels throughout the country.